भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2232
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

बेरोजगारी बढ़ने के कारण

2232. श्री अरविंद सावंतः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 महामारी के बाद मार्च, 2020 से भारत में बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्थायी आधार पर की गई भर्तियों की संख्या क्या है;

(ग) देश में निजी कंपनियों द्वारा वर्तमान में मुहैया कराए जा रहे रोजगार के अवसर की कंपनी-वार संख्या क्या है तथा महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों को कंपनी में रोजगार प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं तथा कंपनी-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मार्च, 2020 और जून, 2021 के बीच देश में कार्यबल से छटनी किए गए लोगों की संख्या के संदर्भ में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कोविड-19 महामारी लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

(ख): केंद्र सरकार में पिछले दो वर्षों के दौरान समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के लिए तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों, अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा की गई भर्तियों की संख्या ' नीचे दी गई है:

समूह	वर्ष	2019-20	2020-21
समूह 'क'	नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या	5,230	3,609
समूह 'ख' और 'ग'	नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या	14,691	68,891

(ग) और (घ): निजी कंपनियों सहित नियोक्ताओं द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाता है। कंपनी-वार आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ड.) और (च): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान (सर्वेक्षण अवधि-जुलाई, 2019 से जून, 2020) आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, महाराष्ट्र सहित 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

अनुबंध

बेरोजगारी बढ़ने के कारण के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 02-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2232 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2019-20 (पीएलएफएस)
1	आंध्र प्रदेश	55.5
2	अरुणाचल प्रदेश	44.3
3	असम	43.2
4	बिहार	39.7
5	छत्तीसगढ	65.4
6	दिल्ली	43.3
7	गोवा	47.3
8	गुजरात	54.7
9	हरियाणा	42.9
10	हिमाचल प्रदेश	70.5
11	झारखंड	53.6
12	कर्नाटक	53.1
13	केरल	45.3
14	मध्य प्रदेश	57.7
15	महाराष्ट्र	55.7
16	मणिपुर	45.5
17	मेघालय	58.6
18	मिजोरम	50.7
19	नागालैंड	44.8
20	ओडिशा	51.9
21	पंजाब	47.8
22	राजस्थान	55.0
23	सिक्किम	68.8
24	तमिलनाडु	55.3
25	तेलंगाना	55.7
26	त्रिपुरा	49.6
27	उत्तराखंड	49.5
28	उत्तर प्रदेश	45.1
29	पश्चिम बंगाल	49.7
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.8
31	चंडीगढ़	45.5
32	दादर और नगर हवेली	72.2
33	दमन और दीव	64.5
34	जम्मू और कश्मीर	52.5
35	लद्दाख	62.7
36	लक्षद्वीप	48.0
37	पुडुचेरी	47.7
	अखिल भारतीय	50.9

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2019-20, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।